मणिपुर: शाह ने की कई लोगों से बात

सरकार ने मृतकों को 10 लाख रुपये मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी की घोषणा की

अर्चिस मोहन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर की चार दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन मंगलवार को कुकी नागरिक समाज के नेताओं से बातचीत करने चुराचांदपुर गए। राज्य में 3 मई से शुरू हुए जातीय संघर्ष में अब तक 80 लोगों की जान जा चुकी है।

चुराचांदपुर में हाल में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच भीषण हिंसा हुई। शाह और केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने चर्च के नेताओं और कुकी समुदाय के बौद्धिक लोगों से मुलाकात की। सरकार ने संघर्ष में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपये के मुआवजे और परिवार के एक सदस्य के लिए नौकरी की घोषणा भी की। मुआवजा राशि का भार केंद्र और राज्य मिलकर वहन करेंगे। यह निर्णय सोमवार देर शाम शाह और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के बीच बैठक के बाद लिया गया। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि पेट्रोल, एलपीजी गैस, चावल तथा अन्य खाद्य उत्पादों की कीमतों में कमी सुनिश्चित की जाएगी।

मंगलवार को शाह ने महिला नेताओं के एक समूह मीरा पैबी के साथ भेंट की और मणिपुर के समाज में महिलाओं की भूमिका की महत्ता को दोहराया। शाह ने इंफाल में सामाजिक नागरिक संगठनों के एक प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार देका भी उनके साथ इंफाल गए हैं।

गृह मंत्री ने की बैठक

- राज्य में 3 मई से शुरू हुए जातीय संघर्ष में अब तक 80 लोगों की जान जा चुकी है
- अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने चर्च के नेताओं और कुकी समुदाय के लोगों से मुलाकात की
- वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की
- शाह ने महिला नेताओं के एक समूह मीरा पैबी के साथ भेंट की और मणिपुर के समाज में महिलाओं की भूमिका की महत्ता को दोहराया

कांग्रेस नेताओं की राष्ट्रपति से मुलाकात

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री इबोबी सिंह समेत कांग्रेस नेताओं ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले उच्च स्तरीय जांच आयोग से इस हिंसा की जांच कराने की मांग करते हुए 12 बिंदुओं वाला एक चार्टर उन्हें सौंपा जो शांति बहाली में मददगार हो सकता है। बाद में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भाजपा और आरएसएस की 'फूट डालो-राज करो' की नीति को मौजूदा हालात का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि गत 22 सालों में यह दूसरा अवसर है जब मणिपुर जल रहा है। पिछली बार ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के कार्यकाल में हुआ था। इबोबी सिंह ने आश्चर्य जताया कि प्रधानमंत्री और शाह अब तक खामोश क्यों बने रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में हिंसा को जारी रहने दिया गया।

उधर ओलिंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू समेत मणिपुर के 11 शीर्ष खिलाड़ियों ने शाह को सौंपे गए एक हस्ताक्षरित पत्र में मांग की कि मौजूदा संकट का हल निकाला जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द हालात सामान्य नहीं हुए तो वे अपने पुरस्कार और तमगे लौटा देंगे। हस्ताक्षर करने वालों में भारोत्तोलक कुंजरानी देवी और मुक्केबाज एल सरिता देवी शामिल हैं। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग-2 को खोलने की भी मांग की। उन्होंने यह मांग भी की कि कुकी उग्रवादी समूहों के विरुद्ध कार्रवाई को निलंबित करने वाले समझौतों को समाप्त किया जाए।

मणिपुर में गत 3 मई को जनजातीय एकता मार्च के बाद जातीय संघर्ष छिड़ गया था। पहाड़ी जिलों में आयोजित मार्च में मैतेई समुदाय के लोग अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांग रहे थे। आरक्षित वन भूमि से कुकी गांववासियों को निकाले जाने के बाद वहां पहले से ही छिटपुट प्रदर्शन चल रहे थे।

मणिपुर की आबादी में 53 फीसदी मैतेई हैं और वे मुख्य रूप से इंफाल घाटी के इलाके में रहते हैं। नागा और कुकी जनजातियां आबादी का शेष 40 फीसदी हैं जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। मिजोरम की सरकार ने केंद्र सरकार से पांच करोड़ रुपये की सहायता राशि मांगी है ताकि उन 8,000 लोगों को तत्काल राहत दी जा सके जिन्होंने मणिपुर से आकर वहां शरण ली है। मणिपुर में हालात सामान्य करने के लिए 10,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। **(साथ में एजेंसियां)**

आरबीआई ने किया आगाह पर ऐप स्टोर पर अब भी ईटीपी

सौरभ लेले

देश में कई अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) अब भी धड़ल्ले से डाउनलोड किए जा सकते हैं। इनमें ज्यादातर ईटीपी विदेश से परिचालन करते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ऐसे ईटीपी के बारे में आगाह कर चुका है और ये केंद्रीय बैंक की सतर्कता सूची (अलर्ट लिस्ट) में हैं। ऐप स्टोरों पर इन ईटीपी की मौजूदगी का कारण यह है कि मोबाइल ऐप्लिकेशन स्टोरों को ऐसे ईटीपी को हटाने के संबंध में स्पष्ट निर्देश नहीं दिए मिले हैं।

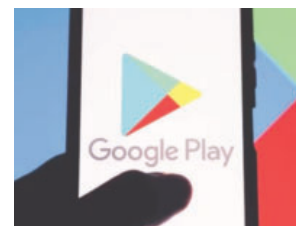

आरबीआई ईटीपी ऐप के बारे में आगाह कर चुका है

आरबीआई ने सितंबर 2022 में एक अलर्ट लिस्ट जारी की थी जिसमें इन ईटीपी को लेकर आगाह किया गया था। तब आरबीआई ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (रिजर्व बैंक) डाइरेक्शंस, 2018 के तहत इन ऐप के जरिये विदेशी मुद्रा में कारोबार करने से सख्त मना किया था। इनके बाद इस वर्ष फरवरी में एक और अलर्ट जारी किया गया था जिसमें 48 ऐसे अनधिकृत ऐप का जिक्र है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा कि आरबीआई की अलर्ट लिस्ट में ऐप के लिए डाउनलोड यूआरएल शामिल नहीं है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि ऐप स्टोर इन ऐप को हटाने को लेकर जारी की गई चेतावनी का स्वतः संज्ञान नहीं ले सकते हैं।

बिज़नेस स्टैंडर्ड को मिली जानकारी के अनुसार अलर्ट लिस्ट जारी होने के बाद प्ले स्टोर से इन ऐप को हटाने पर वित्त मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना-प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के बीच कई बार संवादों का आदान-प्रदान हुआ था। मगर किसी भी सरकारी विभाग या एजेंसी ने इन ईटीपी को हटाने का निर्देश जारी नहीं किया। इसका नतीजा यह हुआ है कि आरबीआई की अलर्ट लिस्ट में शामिल बिनोमो, ओलिंप ट्रेड, एक्सएम-ट्रेडिंग पॉइंट, अवा ट्रेड, ओक्टाएफएक्स, ईटोरो और मेटाट्रेडर5 गूगल प्ले स्टोर पर अब भी मौजूद हैं और आसानी से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि सख्त निगरानी के अभाव में इन ऐप का इस्तेमाल करने वाले लोग न केवल धोखाधड़ी, वित्तीय नुकसान, जानकारी चोरी होने, इनका बेजा इस्तेमाल होने, चोरी और साइबर हमले का शिकार हो सकते है, बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती हैं। आरबीआई कई बार आगाह कर चुका है कि जो लोग अनधिकृत ईटीपी पर कारोबार करते हैं वे फेमा के अंतर्गत अपने खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

लोक नीति शोध संगठन कट्स इंटरनैशनल के निदेशक (शोध) अमोल कुलकर्णी ने कहा कि दोनों अलर्ट लिस्ट में ऐसे कई ईटीपी के नामों का जिक्र था मगर ऐसा लगता है कि इनकी अनदेखी की गई है। कुलकर्णी ने कहा, 'इन ईटीपी पर प्रतिबंध लगाने के लिए ठोस प्रयास नहीं हुआ है। अलर्ट लिस्ट इसलिए जारी की जाती है ताकि लोग जागरूक हो सकें और ऐसी इकाइयों के साथ किसी तरह का लेनदेन न करें। इन ऐप के इस्तेमाल में लिप्त पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।' उन्होंने कहा कि इससे पहले की और देर हो जाए, इस मामले में नियामक, औद्योगिक संगठनों, उपभोक्ता समूहों को एक साथ मिलकर कदम उठाना चाहिए ताकि वे ऐसे संदेहास्पद ऐप के खिलाफ समय रहते कार्रवाई की जा सके।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सितंबर 2022 में फेमा के तहत ओक्टाएफएक्स की बैंक में जमा राशि (21.14 करोड़ रुपये) जब्त कर ली और अप्रैल 2023 में पीएमएलए के तहत 34.75 करोड़ रुपये की जायदाद पर भी ताला जड़ दिया था। ईडी ने टीपी ग्लोबल के जरिये अवैध तरीके से 118.27 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा विनिमय करने वाले कुछ लोगों की जायदाद भी जब्त कर ली थी। इंडसलॉ में संस्थापक पार्टनर अविमुक्त डार ने कहा, 'लोगों को जोखिम की आशंका वाले विदेश से परिचालन करने वाले इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ऐप के माध्यम से विदेशी मुद्रा में कारोबार करने से रोकना सरकार की नीति का हिस्सा है। इन ऐप के साथ जोखिम इसलिए होता है कि कि ये ईटीपी भारत से परिचालन नहीं करते हैं। लोगों के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी होने की स्थिति में सरकार उनकी मदद करने में स्वयं को असमर्थ पा सकती है।'

कर्नाटक के तर्ज पर मप्र का चुनाव लड़ेगी कांग्रेस

संदीप कुमार

कर्नाटक विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विरुद्ध मजबूत जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस की योजना मध्य प्रदेश में भी उन्हीं मुद्दों के साथ चुनावी समर में उतरने की है जिन्होंने दक्षिण भारत के इस अहम राज्य में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने में मदद की।

भ्रष्टाचार, मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी और महिलाओं के विरुद्ध अपराध आदि आगामी दिसंबर में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए अहम मुद्दे होंगे। इनमें भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सबसे अधिक जोर दिया जाएगा।

गत वर्ष 'टेक होम राशन और निःशुल्क खाद्य योजना' में एक बड़ा घोटाला सामने आया था। यह घोटाला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट से उजागर हुआ। यह बात महत्त्वपूर्ण है क्योंकि महिला एवं बाल विकास विभाग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अधीन है।

कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इन दिनों पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में असीमित भ्रष्टाचार हो रहा है और सब इंजीनियर स्तर से मुख्यमंत्री कार्यालय तक पैसा पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'मुख्यमंत्री चौहान ने शपथपत्र में नौ करोड़ रुपये की संपत्ति की घोषणा की है। इतनी संपत्ति कहां से आई?'

कांग्रेस नर्सिंग घोटाले को भी चुनावी मुद्दा बनाएगी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के ग्वालियर खंडपीठ के समक्ष एक याचिका दायर करके नर्सिंग कॉलेजों से जुड़ी धोखाधड़ी की बात कही गई थी।

मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस अध्यक्ष

इस मामले में अपनी नाखुशी जाहिर करते हुए उच्च न्यायालय ने दो-चार कमरों में चलने वाले नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता को लेकर कदम उठाने का आदेश दिया। तब से अब तक करीब 70 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द की गई।

2018-19 में प्रदेश में 448 निजी नर्सिंग कॉलेज थे। महामारी के दौरान इनकी तादाद बढ़कर 667 हो गई। जांच से पता चला कि 600 नर्सिंग कॉलेजों में करीब 500 रिक्तियों में फर्जीवाड़ा किया गया था। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट ने कहा कि जांच करने पर पाया गया कि वहां सबकुछ कागजों पर चल रहा था। जाट कहते हैं, 'मध्य प्रदेश में कमल नाथ के नेतृत्व में कांग्रेस आस्था और विकास के दोहरे एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। यहां तक कि 15 महीने की सरकार में भी कमल नाथ ने धार्मिक पर्यटन को आर्थिक पहलू से जोड़ने का प्रयास किया था। इस बार भी कांग्रेस किसानों, महिलाओं और युवाओं तथा समाज के विश्वास को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है।'

एक सूत्र के मुताबिक, 'पार्टी ने 100 सीटों पर प्रत्याशी तय कर लिए हैं। इस चुनाव में कांग्रेस को भाजपा की अंदरूनी लड़ाई से भी फायदा मिल सकता है। अगर मौजूदा विधायकों समेत भाजपा के कुछ नेता कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते दिखें तो भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए।'

पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी ने हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है।

कांग्रेस ने इन चुनावों में मतदाताओं से पांच वादे किए हैं: 500 रुपये में गैस सिलिंडर, 18 वर्ष से अधिक आयु की हर महिला को प्रति माह 1,500 रुपये, 100 यूनिट बिजली मुफ्त और 200 यूनिट तक बिजली आधी कीमत पर, किसानों की कर्ज माफी और पुरानी पेंशन बहाल करना।

राजनीतिक विश्लेषक प्रभु पटेरिया कहते हैं कि कांग्रेस को इनसे लाभ मिल सकता है क्योंकि ये योजनाएं मतदाताओं को लुभा रही हैं। पटेरिया कहते हैं, 'मध्य प्रदेश के विधान सभा चुनाव अब तक निःशुल्क उपहारों की घोषणा से बचे हुए थे। लेकिन इस बार कांग्रेस और भाजपा दोनों की ओर से ऐसी घोषणाएं हो रही हैं।' वह कहते हैं कि भाजपा की आंतरिक लड़ाई और सत्ता विरोधी माहौल भी पार्टी के खिलाफ जा सकता है।

वह कहते हैं, 'अभी तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस को ही क्षत्रपों की पार्टी माना जाता था लेकिन अब यह समस्या भाजपा में भी नजर आने लगी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का खेमा अपने लाभ में किसी तरह की कमी नहीं चाहता। चौहान का अपना जनाधार है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की भी अनदेखी नहीं की जा सकती है।'

आज़ादी का अमृत महोत्सव
www.bankofbaroda.in
बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

सूचना

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा आयोजित होने वाली 27वीं वार्षिक आम बैठक

बैंक के शेयरधारक कृपया नोट करें कि इस संबंध में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप बैंक की 27वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 07 जुलाई, 2023 को भारतीय समयानुसार पूर्वाह्न 11:00 बजे बैठक की नोटिस में उल्लिखित किए जाने वाले कारोबार के संचालन हेतु **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम)** द्वारा आयोजित की जाएगी।

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसरण में वार्षिक आम बैठक हेतु नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाएंगी जिनके ईमेल पते बैंक/डिपॉजिटरी सहभागी (गियों) के साथ पंजीकृत हैं। डीमैटरलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों जिनके ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं, से अनुरोध है कि अपने डिपॉजिटरी सहभागियों के माध्यम से संबंधित डिपॉजिटरी के साथ अपना ई-मेल पता और मोबाइल नंबर पंजीकृत करवाएं। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपने धारित शेयरों को डीमैट करवा लें/ बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को **einward.ris@kfintech.com** पर अपने ई-मेल पते और मोबाइल नंबर की जानकारी दें। 27वीं वार्षिक आम बैठक की नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 की प्रति बैंक की वेबसाइट **www.bankofbaroda.in**, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट और आरटीए की वेबसाइट **https://evoting.kfintech.com** पर भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

वार्षिक आम बैठक की नोटिस में उल्लिखित कारोबार के संबंध में शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से दूर से अपना मत डालने का अवसर मिलेगा। डीमैटरलाइज्ड और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों तथा ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, द्वारा दूर से मतदान डालने संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख शेयरधारकों को भेजे जाने वाले नोटिस में किया जाएगा। इससे संबंधित विवरण बैंक की वेबसाइट पर भी होंगे। शेयरधारकों से अनुरोध है कि उक्त विवरण के लिए **www.bankofbaroda.in** को देखें।

शेयरधारक कृपया नोट करें कि उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसरण में बैंक द्वारा शेयरधारकों को वार्षिक आम बैठक की नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां नहीं भेजी जाएगी।

शेयरधारकों से यह भी अनुरोध कि वर्ष 2022-23 के लाभांश को प्राप्त करने के लिए फोलियो/ डीमैट खाते में अपने बैंक खाते का विवरण अद्यतन कराएं।

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा
संजीव चड्ढा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : मुंबई
दिनांक : 31.05.2023

34/23-24

हरिद्वार से दिल्ली लौटे पहलवान

महिला खिलाड़ियों के उत्पीड़न के विरोध में मंगलवार को विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया हरिद्वार में गंगा नदी में अपने पदक प्रवाहित करने पहुंचे। लेकिन श्री गंगा सभा ने हरकी पैड़ी पर ऐसा करने से उन्हें रोक दिया।

पहलवानों से मिलने के लिए हरकी पैड़ी पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेश टिकैत पहुंचे। उन्होंने पहलवानों को समझाया तथा आश्वासन दिया कि वह पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए वार्ता करेंगे। नरेश टिकैत की बात मानने के बाद पहलवान करीब पौने दो घंटे के बाद दिल्ली लौट गए।

दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने और जंतर-मंतर में धरना स्थल से हटाए जाने के बाद पहलवानों ने मंगलवार को कहा कि वे कड़ी मेहनत से जीते अपने पदक गंगा नदी में बहा देंगे और इंडिया गेट पर 'आमरण अनशन' पर बैठेंगे। रियो ओलिंपिक 2016 की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक बयान में कहा था कि पहलवान मंगलवार को हरिद्वार में गंगा नदी में अपने पदक प्रवाहित करेंगे। **एजेंसियां**

आज़ादी का अमृत महोत्सव
www.bankofbaroda.in
बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

निविदा सूचना

बैंक ऑफ़ बड़ौदा निम्नलिखित के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है:

क्रम सं.	निविदा का नाम	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख
1	यूनिवर्सल रिकंसिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम की आपूर्ति, क्रियान्वयन और रखरखाव के लिए आरएफपी	27.06.2023

इससे संबंधित विवरण बैंक की वेबसाइट **www.bankofbaroda.in** के निविदा खंड में और GeM पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

"परिशिष्ट", यदि कोई हो, को बैंक की वेबसाइट **www.bankofbaroda.in** के निविदा खंड में प्रकाशित किया जाएगा। प्रस्ताव को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले बोलीकर्ता इसे अवश्य देख लें।

स्थान: मुंबई
दिनांक: 31.05.2023
मुख्य महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)

35/23-24

insecticides (INDIA) LIMITED
TRACTOR BRAND IIL

पंजीकृत कार्यालय: 401-402, लूसा टावर, आज़ादपुर कमर्शियल कॉम्प्लैक्स, दिल्ली-110 033; टेलीफैक्स: 011-27679700-05
वेबसाइट: www.insecticidesindia.com, इमेल: investor@insecticidesindia.com, CIN: L65991DL1996PLC083909

31 मार्च, 2023 को समाप्त वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का निष्कर्ष

(₹ लाख में, ईपीएस के अतिरिक्त)

क्र. सं.	विवरण	एकल					समेकित				
		तिमाही की समाप्ति			वार्षिक समाप्ति		तिमाही की समाप्ति			वार्षिक समाप्ति	
		31-03-23 (लेखापरीक्षित)	31-12-22 (अलेखापरीक्षित)	31-03-22 (लेखापरीक्षित)	31-03-23 (लेखापरीक्षित)	31-03-22 (लेखापरीक्षित)	31-03-23 (लेखापरीक्षित)	31-12-22 (अलेखापरीक्षित)	31-03-22 (लेखापरीक्षित)	31-03-23 (लेखापरीक्षित)	31-03-22 (लेखापरीक्षित)
1	परिचालन से कुल आय	30,230.94	35,690.66	28,006.71	1,80,259.24	1,50,822.95	30,230.94	35,690.66	28,006.71	1,80,259.24	1,50,822.95
2	कर अदायगी के पूर्व शुद्ध लाभ	(3,902.73)	1,241.74	2,809.51	8,360.71	14,096.54	(3,931.73)	1,244.91	2,803.75	8,382.91	14,137.23
3	कर अदायगी के पश्चात शुद्ध लाभ	(2,900.82)	933.39	2,239.24	6,298.75	10,702.13	(2,929.66)	936.56	2,233.48	6,321.12	10,742.82
4	अवधि के दौरान कुल समेकित आय [इस अवधि के लिए लाभ (कर के बाद) और अन्य समेकित आय (कर के बाद)]	(2,980.79)	890.43	2,359.32	6,327.55	10,800.84	(3,008.36)	894.27	2,354.96	6,353.03	10,843.00
5	पेड-अप इक्विटी शेयर पूँजी (वास्तविक मूल्य ₹10/- प्रति शेयर)	2,959.78	2,959.78	1,973.19	2,959.78	1,973.19	2,959.78	2,959.78	1,973.19	1,973.19	1,973.19
6	पिछले वित्तीय वर्ष के तुलना पत्र में प्रदर्शित लेखापरीक्षित आरक्षित निधि (पूनर्मूल्यन निधि के अतिरिक्त)	-	-	-	88,609.09	84,748.02	-	-	-	88,869.19	84,987.93
7	प्रति शेयर आय (वास्तविक मूल्य ₹10/- प्रति शेयर) (वार्षिक नहीं)										
	आधारभूत	(9.80)	3.15	7.57	21.28	36.04	(9.90)	3.16	7.55	21.36	36.17
	मिश्रित	(9.80)	3.15	7.57	21.28	36.04	(9.90)	3.16	7.55	21.36	36.17

नोट:

a) उपरोक्त अवतरण, सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रगटीकरण आवश्यकताएँ) विनिमयन, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में 31 मार्च, 2023 के अंत में दाखिल तिमाही और वार्षिक समाप्ति का लेखापरीक्षित एकल और समेकित वित्तीय परिणामों का सार है। एकल और समेकित वित्तीय परिणाम और व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com, www.nseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.insecticidesindia.com पर उपलब्ध है।

b) उपरोक्त लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम भारतीय लेखा मानक (इंड एएस), कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी दिशानिर्देश) के द्वारा लागू दिशानिर्देशों के अनुसार है। इंड-एएस कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 और उसके बाद के संशोधनों के तहत निर्धारित हैं।

c) सदस्यों से अनुमोदन के अनुसरण में, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹2500 लाख जिसमें 2,50,00,000 इक्विटी शेयर्स हैं जिसका अंकित मूल्य ₹10/- प्रति शेयर है से बढ़कर ₹3500 लाख हो गया था जिसमें 3,50,00,000 इक्विटी शेयर्स शामिल थे जिसका अंकित मूल्य ₹10/- प्रति शेयर था। इसके अलावा, 06 अक्टूबर, 2022 को आवंटन समिति ने ₹10/- प्रति शेयर के अंकित मूल्य के 98,65,946 इक्विटी शेयर्स को प्रत्येक दो इक्विटी शेयर के लिए ₹10/- अंकित मूल्य के एक बोनस इक्विटी शेयर के अनुपात में आवंटित किया है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है और प्रतिभूति प्रीमियम से ₹9,86,59,460 की राशि का पूंजीकरण किया गया है। बोनस शेयर बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में प्रभावी कार्य दिवस 17 अक्टूबर, 2022 पर सूचीबद्ध थे। इसने उपर्युक्त वित्तीय परिणामों को प्रभावित नहीं किया है, प्रति शेयर आय को छोड़कर, जिसे इंड-एएस 33 'प्रति शेयर कमाई' के अनुसार प्रस्तुत सभी अवधि में बोनस इश्यू के लिए समायोजित किया गया है।

d) समूह द्वारा "आईआईएल बायोलॉजिकल्स लिमिटेड" नाम से पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को 15 जुलाई, 2022 को शामिल किया गया था। पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी सभी प्रकार के आर्गेनिक और जैविक कृषि उर्वरकों, जैव-कीटनाशकों, जैव-नियंत्रण एजेंटों या किसी अन्य संबद्ध उत्पादों के निर्माण, बिक्री, खरीद आदि का व्यवसाय करेगी।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
इन्सेक्टिसाइड्स (इंडिया) लिमिटेड
ह-
(राजेश कुमार अग्रवाल)
प्रबंध निदेशक
DIN-00576872
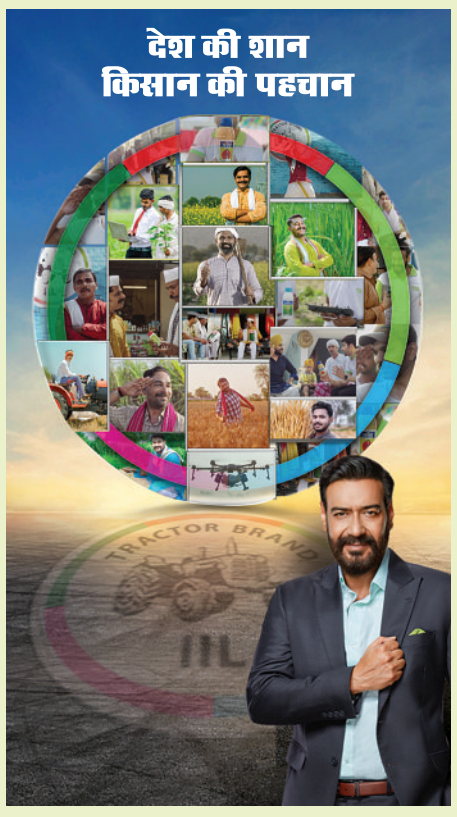
स्थान: दिल्ली
दिनांक: 30/05/2023